राज्यों को केन्द्रीय योजनाओं का अन्तरण

1724. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिथा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री 19 दिसंबर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3280 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राज्य सरकारों को पूर्ण रूप से अंतरित किये जाने का विचार है और इसके वित्तीय निहितार्थ क्या हैं;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रहेंगी;

(ग) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऊपर उल्लिखित श्रेणी की कौन कौन सी योजनायें चल रही हैं; और

(घ) इस अभियान के उद्देश्य क्या हैं और इसके वित्तीय निहितार्थ क्या है तथा इससे राज्य को किस प्रकार का लाभ होगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराज) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) ने 23 और 24 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में, अन्य मतों के साथ-साथ, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (नरसिंह राव समिति) से सम्बद्ध राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था जिसमें 125 ऐसी योजनाओं को रखने और 113 योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरण करने की सिफारिश की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि 113 योजनाओं को जिन्हें 1987 की रिपोर्ट को लिखते समय कार्यान्वित किया जा रहा था, केन्द्रीय निधि अंश सहित राज्यों को हस्तांतरित किया जाए जिन्हें आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता के फार्मूले से बाहर विमोचित किया जायेगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद के उपरोक्त निर्णय के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि 1991–92 स्तर पर केन्द्रीय निधि अंश सहित 1992–93 में इन योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में वित्तीय निहितार्थों का पता केवल तभी चलेगा जब इसको अंतिम रूप दे दिया जायेगा और केन्द्रीय बजट पारित होने के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रभावित निधियों का हस्तांतरण कर दिया जायेगा।

(ख) भारत सरकार द्वारा रखी गई 125 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (जो नरसिंह राव समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के समय विद्यमान थी) की एक सूची संलग्न है [देखिए परिशिष्ट. 162, अनुपत्र संख्या 42]।

(ग) ऐसी योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) राज्यों को इन योजनाओं का हस्तांतरण, विकासात्मक योजनाओं की क्रियान्विति में राज्यों को और अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए आयोजना में बढ़ते हुए विकेन्द्रीकरण हेतु आठवीं योजना नीति के अनुरूप है।

Setting up of working group on Housing

1725. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Working Group on Housing;

(b) if so, what are its terms of reference and composition; and

(c) by when it is expected to submit its report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ):

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Special Category Status to Goa

1726. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Goa has made a demand for special category status in view of its weak resource base;

(b) if so, whether Government propose to give special category status to Goa in view of its resources crunch since Goa is mainly depending upon the income from tourism sector only?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) States included among the Special Category States, for the purpose of Central Assistance for Plan Financing, are those which have a strategic location on the border with neighbouring countries and are hilly states, some with large tribal population and/or which have been constituted out of former small Union Territories districts, with limited and weak resource base compared to their development needs.

Goa, though carved out of erstwhile Union Territory, has no such handicap. It is one of the richer States with a well developed fiscal framework and possesses a known potential for resource mobilisation from tourism, minerals and mineral based industries. As such the State of Goa does not qualify for the status of Special Category States.

Schemes for Development of Hill areas in the Eighth Plan

1727. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether special schemes are being formulated for the development of Hill areas in the Eighth Five Year plan;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) Hill Areas Development Programme is likely to continue in the designated Hill Areas and the Western Ghats Region during the Eighth Five Year Plan also. The objective of the programme is to ensure socio-economic development of the hill communities in harmony with ecological concerns and schemes are likely to be formulated accordingly.

Cut in the Annual Plan of Uttar Pradesh

1728. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Uttar Pradesh in a letter to the Prime Minister has urged him to reconsider the decision of the Planning Commission to cut down the State's Annual Plan, as per the news item titled "Kalyan for bigger Annual Plan", appeared in the Hindustan Times of the 30th January, 1992;

(b) if so, what are the details thereof and the extent of cuts suggested by the Central Government on the Annual Plan of Uttar Pradesh;